हिन्दी दैनिक

# लखनऊ जंक्शन

RNI NO.-UPHIN/2015/64743 Email-lkojunction@gmail.com

वर्ष: 11 अंक: 124 लखनऊ, मंगलवार 23 दिसम्बर 2025 पृष्ठ: 04 मूल्य: 01 रूपये

## योगी सरकार ने विधानसभा में प्रस्तुत किया 24,496.98 करोड़ का अनुपूरक बजट

### विकास की रफ्तार बनाए रखने और प्राथमिक क्षेत्रों को मजबूती देने पर सरकार का फोकस

### अनुपूरक बजट मूल बजट का 3.03 प्रतिशत, 18,369 करोड़ राजस्व व्यय और 6,127 करोड़ पूंजीगत व्यय का प्रावधान

**लखनऊ ब्यूरो**

लखनऊ, 22 दिसंबर। योगी सरकार ने सोमवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए 24,496.98 करोड़ का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए कहा कि यह अनुपूरक बजट प्रदेश में विकास की निरंतरता बनाए रखने, आवश्यक क्षेत्रों में अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने और बदलती जरूरतों के अनुरूप योजनाओं को गति देने के उद्देश्य से लाया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्ष 2025–26 के लिए प्रदेश का मूल बजट 808,736.06 करोड़ का था, जबकि प्रस्तुत अनुपूरक बजट मूल बजट के अनुपात में 3.03 प्रतिशत है। अनुपूरक बजट को मिलाकर वित्तीय वर्ष 2025–26 का कुल बजट अब 833,233.04 करोड़ का हो गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट विकासात्मक प्राथमिकताओं को और अधिक सुदृढ़ करने पर केंद्रित है।

**राजस्व और पूंजीगत व्यय का संतुलित प्रावधान**

प्रस्तुत अनुपूरक बजट में राजस्व व्यय के रूप में 18,369.30 करोड़, पूंजीगत व्यय के रूप में 6,127.68 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सरकार का उद्देश्य राजस्व आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ–साथ पूंजीगत निवेश को बढ़ाकर आधारभूत ढांचे को मजबूत करना है।

**उद्योग, ऊर्जा और स्वास्थ्य को मिला बजट**

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अनुपूरक बजट में प्रदेश की आर्थिक प्रगति और जनकल्याण से जुड़े प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। इसके अंतर्गत औद्योगिक विकास के लिए 4,874 करोड़, पावर सेक्टर के लिए 4,521 करोड़, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 3,500 करोड़, नगर विकास के लिए ध्1,758.56 करोड़, तकनीकी शिक्षा के लिए 639.96 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है।

**महिला, शिक्षा, सौर ऊर्जा और कृषि से जुड़े क्षेत्रों को भी बल**

अनुपूरक बजट में सामाजिक और भविष्य उन्मुख क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इसके तहत, महिला एवं बाल विकास के लिए 535 करोड़, यूपीनेडा (सौर एवं नवीकरणीय ऊर्जा) के लिए 500 करोड़, मेडिकल एजुकेशन के लिए 423.80 करोड़, गन्ना एवं चीनी मिल क्षेत्र के लिए 400 करोड़ की बजटीय व्यवस्था की गई है।

**एफआरबीएम सीमा का पूर्ण अनुपालन, जीएसडीपी में ऐतिहासिक वृद्धि**

वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि योगी सरकार ने एफआरबीएम (थ्स्ठड) अधिनियम की सीमा का हमेशा पालन किया है और किसी भी स्तर पर वित्तीय अनुशासन से समझौता नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के पत्रक के अनुसार उत्तर प्रदेश की जीडीपी (GSDP) 31.14 लाख करोड़ आंकी गई है, जो पहले के अनुमानों से अधिक है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में उभर रहा है, जो राज्य की मजबूत आर्थिक स्थिति को दर्शाता है।

**विकास की गति बनाए रखने के लिए प्रस्तुत हुआ अनुपूरक बजट**

जब किसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि व्यय की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त हो जाती है, तब अनुपूरक अनुदान की मांग विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। कई बार नई मदों पर व्यय की आवश्यकता होती है या योजनाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन के कारण विधानमंडल की स्वीकृति अनिवार्य हो जाती है।

## यूपी में कोडीन कफ सिरप से एक भी मौत नहीं : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

### विधानसभा में सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला, कोडीन कफ सिरप पर किया बेनकाब बोले– यूपी में कोडीन सिरप के अवैध नेटवर्क के तार सीधे समाजवादी पार्टी से जुड़े

**लखनऊ ब्यूरो**

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कोडीन कफ सिरप प्रकरण पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी पर करारा प्रहार करते हुए सरकार का पक्ष मजबूती से रखा। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि उत्तर प्रदेश में कोडीन कफ सिरप से एक भी मौत नहीं हुई है, लेकिन अवैध डायवर्जन, ट्रेडिंग और स्टोरेज के इस पूरे नेटवर्क के तार समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों तक पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष और सपा सदस्यों के हंगामे पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रश्न क्या है और मुद्दा क्या बनाया जा रहा है। इसका फर्क समझना चाहिए। सदन की गरिमा बनाए रखना विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहावत 'चोर की दाढ़ी में तिनका' का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष की बेचैनी खुद बहुत कुछ बयां कर रही है।

**कोडीन से यूपी में कोई मौत नहीं, झूठ फैलाया जा रहा**

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि कोडीन युक्त कफ सिरप को लेकर प्रदेश में मौत की कोई भी घटना शासन के संज्ञान में नहीं है। यह पूरा मामला इललीगल डायवर्जन का है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में न तो कोडीन कफ सिरप का उत्पादन होता है और न ही इसका गैरकानूनी निर्माण। यूपी में केवल स्टॉकिस्ट और होलसेलर हैं। इसका उत्पादन मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में होता है, जबकि जिन मौतों की बात की जा रही है, वे अन्य राज्यों विशेषकर तमिलनाडु में बने सिरप से जुड़ी हैं।

**2016 में सपा सरकार ने जारी किया सबसे बड़े होलसेलर का लाइसेंस**

मुख्यमंत्री ने सदन में बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े कोडीन कफ सिरप होलसेलर को 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने लाइसेंस जारी किया था। एसटीएफ ने उसी नेटवर्क को पकड़ा है। उन्होंने कहा कि देश में "दो नमूने" हैं, एक दिल्ली में और दूसरा लखनऊ में बैठता है और जब भी कोई गंभीर चर्चा होती है तो देश छोड़कर भाग जाते हैं। यही हाल "बबुआ" का भी है। आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे और बबुआ इंग्लैंड सैरसपाटे पर निकल जाएंगे।

**नेता प्रतिपक्ष पर तंजकृइस उम्र में भी झूठ बुलवाते हैं समाजवादी**

मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इस उम्र में व्यक्ति सच बोलने का आदी हो जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस उम्र में भी उनसे झूठ बुलवाती है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने लंबे समय तक स्पीकर के रूप में सदन को आगे बढ़ाया है, इसलिए उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी।

**सपा नेताओं की पढ़ाई–लिखाई पर सवाल**

मुख्यमंत्री ने कहा कि कफ सिरप का सेवन बिना चिकित्सकीय परामर्श के संभव नहीं है। खांसी होने पर हर कोई कफ सिरप लेता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। इस पर चेतावनी भी अंकित होती है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों का पढ़ाई–लिखाई से कोई वास्ता नहीं है, इसलिए वे ऐसे गैर–जिम्मेदाराना बयान देते हैं।

**एसआईटी, एसटीएफ और एफएसडीए की ताबड़तोड़ कार्रवाई**

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई है। अब तक 79 अभियोग दर्ज हुए है, 225 अभियुक्त नामजद हैं, 78 गिरफ्तारियां और 332 फर्मों पर छापेमारी की जा चुकी है। 136 फर्मों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। कोर्ट ने भी एनडीपीएस के तहत कार्रवाई को उचित ठहराया है।

**सपा से जुड़े 'किंग पिन' का नाम सदन में उजागर**

मुख्यमंत्री ने सदन में सबूतों के साथ बताया कि आलोक सिपाही जो इस प्रकरण का किंग पिन है, पक्का सपाई है। उन्होंने फोटो दिखाते हुए कहा कि आरोपी अमित यादव, अखिलेश यादव के साथ तस्वीर में दिखाई देता है और समाजवादी पार्टी की युवजन सभा से जुड़ा रहा है। यही नहीं, विभोर राणा का लाइसेंस समाजवादी सरकार में जारी हुआ था, जबकि

आलोक सिपाही को भाजपा सरकार ने बर्खास्त किया था।

**अवैध लेन–देन लोहिया वाहिनी के पदाधिकारी के खाते से**

मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच में यह भी सामने आया है कि अवैध लेन–देन लोहिया वाहिनी के एक पदाधिकारी के खाते के माध्यम से हुआ है। शुभम जायसवाल, अमित यादव, मिलिंद यादव, मनोज यादव, राजीव यादव और मुकेश यादव जैसे नाम इस अवैध नेटवर्क में सामने आए हैं। अमित यादव की 2024 में दुबई यात्रा का भी उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हर कड़ी की जांच हो रही है।

**'जब कार्रवाई होगी तो सपा वाले ही फातिहा पढ़ने जाएंगे'**

विपक्ष के हंगामे पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब समाजवादी पार्टी से जुड़े आरोपियों पर कार्रवाई होगी तो सपा के लोग ही सबसे पहले फातिहा पढ़ने जाएंगे। उन्होंने दो टूक कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी को चेतावनी देते हुए कहा कि समय आने पर बुलडोजर कार्रवाई भी होगी, तब चिल्लाइएगा नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार कानून के तहत पूरी सख्ती से कार्रवाई करेगी।

## वन भूमि अतिक्रमण पर पर बोली सुप्रीम कोर्ट-मूक दर्शक की तरह बैठी है उत्तराखंड सरकार

**एजेंसी**

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने वन भूमि पर अतिक्रमण के मामले में सोमवार को उत्तराखंड सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि राज्य सरकार और उसके अधिकारी ''मूक दर्शक'' की तरह बैठे रहे और अदालत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया। भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की अवकाशकालीन पीठ ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को एक जांच समिति गठित करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा, ''हमारे लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उत्तराखंड सरकार और अधिकारी अपनी आंखों के सामने वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को मूक दर्शक की तरह देख रहे हैं। इसलिए हम इस मामले पर स्वतः संज्ञान ले रहे हैं।'' न्यायालय ने कहा, ''उत्तराखंड के मुख्य सचिव और प्रधान संरक्षण सचिव को एक तथ्य अन्वेषण समिति गठित करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। निजी पक्षों को किसी भी

प्रकार का तीसरा पक्ष बनाने से रोका जाता है और कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा।'' उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आवासीय मकानों को छोड़कर खाली पड़ी जमीनों पर वन विभाग का कब्जा होगा। न्यायालय ने इस मामले पर अगली सुनवाई छुट्टियों के बाद तय की। उच्चतम न्यायालय उत्तराखंड में वन भूमि के एक बड़े हिस्से पर अवैध कब्जे से संबंधित अनीता कांडवाल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

## 40 साल में पहली बार इस सीट पर खिला कमल, महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत की ये कहानी पता है?

**एजेंसी**

नयी दिल्ली। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ महायुती गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की है। बीजेपी, शिवसेना, सिंधे गुट और एनसीपी ख्संगीत, अजीत पवार गुट के गठबंधन ने 288 नगर परिषद और नगर पंचायतों में से 207 जगहों पर अध्यक्ष पद जीतकर अपना दबदबा बरकरार रखा। इस जीत में सबसे बड़ी हिस्सेदारी बीजेपी की रही। जिसने अकेले 117 अध्यक्ष पद अपने नाम किए और गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इस चुनावी नतीजों में नागपुर जिले की कामटी नगर पालिका परिषद की जीत सबसे ज्यादा चर्चा में रही। यहां बीजेपी ने 40 साल के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रत्याशी अजय अग्रवाल ने कांग्रेस उम्मीदवार शाकुर नगानी को हराकर ना सिर्फ अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया बल्कि कांग्रेस के मजबूत गढ़ को भी ध्वस्त कर दिया। कामटी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए हुआ यह चुनाव आखिर तक सस्पेंस से भरा रहा। मतगणना के शुरुआती दौर में कांग्रेस उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए थे। लेकिन आखिरी राउंड में पासा पलटा और बीजेपी ने बाजी मार ली। बीजेपी प्रत्याशी अजय अग्रवाल ने कांग्रेस के शाकुर नगानी को महज 103 वोटों के मामूली अंतर से हरा दिया। वहीं हार के बाद कांग्रेस के शाकुर नगानी ने चुनाव नतीजों में गड़बड़ी का आरोप लगाया। नागपुर जिले में कामठी विधानसभा अध्यक्ष पद सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, क्योंकि उम्मीदवारों के बीच तीखी जुबानी जंग छिड़ गई।

## ओड़िशा: सरकारी जमीन पर धान की कटाई को लेकर दो गुटों में झड़प के बाद तनाव, बीएनएसएस की धारा 163 लागू

**एजेंसी**

केंद्रापाड़ा। ओडिशा में केंद्रापाड़ा जिले के पेटचेला गांव में सरकारी जमीन पर धान की कटाई को लेकर दो गुटों में झड़प के बाद तनाव बना हुआ है। केंद्रपाड़ा के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) ने कानून–व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए कृषि भूमि पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)

की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पेटचेला गांव के हाबू नंदा ने 24 एकड़ सरकारी जमीन ली थी। लगभग 20 किरायेदार कई सालों से उनकी अनुमति से उस जमीन पर ध्ान की खेती कर रहे थे। कुछ दिन पहले उसने वह जमीन शिशिर कुमार राउत को सौंप दी और किरायेदारों को निर्देश दिया कि वे धान उन्हें दें। धान की कटाई के दौरान शिशिर राउत और उनके साथियों ने लंबे समय से खेती कर रहे किसानों के धान इकट्ठा करने का विरोध किया, जिससे 20 दिसंबर से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इस मुद्दे पर दोनों गुटों के बीच मामूली झड़प भी हुई।जांबू मरीन पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप किया लेकिन तनाव बना रहा। पुलिस ने बाद में यह मामला एसडीएम अरुण कुमार नायक के संज्ञान में लाया, जिन्होंने कानून–व्यवस्था बनाए रखने के लिए बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी। अतिरिक्त पुलिस अध्ीक्षक सुधाकर साहू ने बताया कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की दो प्लाटून इलाके में तैनात की गई हैं। आगे तनाव को बढ़ने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है और दोनों पक्षों को उस जमीन में जाने से रोक दिया गया है। महाकालपाड़ा तहसीलदार रबींद्रनाथ आचार्य ने कहा कि चूंकि यह जमीन राज्य सरकार की है इसलिए स्थानीय तहसील प्रशासन ने धान की कटाई की और उस पर कब्जा कर लिया।

## भारत-न्यूजीलैंड के बीच एफटीए पर मुहर, पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन से फोन पर की बात

**एजेंसी**

नयी दिल्ली। न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को बेहद गहरा करेगा, बाजार पहुंच को व्यापक करेगा और निवेश प्रवाह को बढ़ावा देगा। भारत ने सोमवार को बयान में यह बात कही। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और न्यूजीलैंड के उनके समकक्ष क्रिस्टोफर लक्सन ने दोनों देशों के बीच एक ''ऐतिहासिक'' मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत संपन्न होने की सोमवार को घोषणा की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने फोन पर बातचीत की जिसके बाद मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर वार्ता संपन्न होने की घोषणा की गई। विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा, '' दोनों नेताओं ने ऐतिहासिक, महत्वाकांक्षी एवं पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत–न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के सफल समापन की संयुक्त रूप से घोषणा की।'' इसमें कहा गया है कि दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जाहिर की कि नौ महीने के रिकॉर्ड समय में मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) का संपन्न होना दोनों देशों के बीच संबंधों को और गहरा करने की साझा महत्वाकांक्षा एवं राजनीतिक इच्छाशक्ति को दर्शाता है। विदेश मंत्रालय ने कहा, '' यह मुक्त व्यापार समझौता, द्विपक्षीय आर्थिक जुड़ाव को गहरा करेगा, बाजार पहुंच को व्यापक बनाएगा, निवेश प्रवाह को बढ़ावा देगा तथा दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को मजबूत करेगा। साथ ही यह, दोनों देशों के नवोन्मेषकों, उद्यमियों, किसानों, लघु एवं मध्यम उद्यमों, छात्रों तथा युवाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसर खोलेगा।''इसमें कहा गया है कि दोनों नेताओं ने अगले पांच वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के साथ–साथ अगले 15 वर्ष में न्यूजीलैंड के भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने को लेकर विश्वास व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा, '' दोनों नेताओं ने खेल, शिक्षा एवं लोगों के बीच संबंधों जैसे द्विपक्षीय सहयोग के अन्य क्षेत्रों में हासिल की गई प्रगति का भी स्वागत किया। साथ ही भारत–न्यूजीलैंड साझेदारी को और मजबूत करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।''

## पश्चिम बंगाल: ममता बनर्जी ने एसआईआर से पहले बूथ–स्तरीय सहायकों के लिए कार्यसूची की तैयार

**एजेंसी,** कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दूसरे चरण के दौरान पार्टी के बूथ–स्तरीय सहायकों (बीएलए) को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में सोमवार को विस्तृत निर्देश जारी किये। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में एक जन सभा को संबोधित करते हुए बनर्जी ने चरणबद्ध कार्यसूची की रूपरेखा प्रस्तुत की और सतर्कता, पारदर्शिता और जमीनी स्तर पर भागीदारी पर जोर दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची से बाहर न रह जाए।मुख्यमंत्री ने कहा कि मृत, स्थानांतरित और अनुपस्थित मतदाताओं की सूचियां आधिकारिक वेबसाइटों पर प्रकाशित की जाएंगी और साथ ही जिला, उपमंडल, ब्लॉक और नगरपालिका कार्यालयों में भी प्रदर्शित की जाएंगी। बीएलए को इन सूचियों के आधार पर घर–घर जाकर सत्यापन करने का निर्देश दिया गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि हटाए गए या अनुपस्थित के रूप में दिखाये गये कोई भी मतदाता वास्तव में दिए गए पते पर रह रहे हैं या नहीं।यदि ऐसे मतदाता पाए जाते हैं, तो बीएलए को उन्हें पुनः नामांकन के लिए फॉर्म 6 और अनुलग्नक 4 को निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) को जमा करने में सहायता करनी चाहिए। बनर्जी ने बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा ष्समान्यष् के रूप में चिह्नित मतदाताओं की ओर ध्यान दिलाया।

## संक्षिप्त समाचार

### वर्ष 2025 में रियल्टी क्षेत्र में रिकॉर्ड 10.4 अरब डॉलर का संस्थागत निवेश आया : जेएलएल

**एजेंसी**

नयी दिल्ली। भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र में 2025 के दौरान संस्थागत निवेश 17 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 10.4 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंचने का अनुमान है। जेएलएल ने यह जानकारी देते हुए कहा कि बेहतर प्रतिफल के लिए घरेलू और विदेशी, दोनों निवेशकों ने वाणिज्यिक और आवासीय परियोजनाओं में पूंजी लगाई है। रियल एस्टेट सलाहकार जेएलएल इंडिया ने सोमवार को जारी आंकड़ों में बताया कि 2025 में भारतीय रियल एस्टेट में कुल संस्थागत निवेश का 52 प्रतिशत योगदान घरेलू निवेशकों का रहा। बाकी 48 प्रतिशत विदेशी कोषों से आया। आंकड़ों के मुताबिक, भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र में संस्थागत निवेश का अनुमान 1,040 करोड़ अमेरिकी डॉलर है, जबकि 2024 में यह 887.8 करोड़ डॉलर था। सलाहकार ने कहा कि विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में कार्यालय खंड ने संस्थागत निवेश में फिर से अपना वर्चस्व कायम किया।

# संपादकीय

## आरक्षण देने में भूल हुई या बेईमानी

देश में आरक्षण व्यवस्था सामाजिक न्याय की रीढ़ मानी जाती है, लेकिन जब उसी व्यवस्था के साथ योजनाबद्ध छेड़छाड़ होने लगे, तो यह लोकतंत्र और संविधान दोनों के लिए गंभीर खतरा बन जाती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती के घ्जारी विज्ञापन में जो हुआ, उसने यह साबित कर दिया कि अब आरक्षण की बेईमानी ही नहीं बल्कि खुलेआम डकैती की जा रही है। इसके पीछे इडब्लूएस है?। शायद यही कारण था मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर असहमति जताई थी। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के विज्ञापन में कुल 7994 पद के सापेक्ष ओबीसी वर्ग को मिलने वाली 27 प्रतिशत आरक्षित सीटों के अनुसार लगभग 2158 पद होते हैं लेकिन ओबीसी को 1441 पद ही दिए गये। इडब्लूएस को अलग से पद देने की जगह ओबीसी की सीटों से दे दिया गया। ओबीसी की चोरी की गई 717 पदों को ईडब्ल्यूएस के रूप में दिया गया। यह बेईमानी किसी को समझ में न आए इसके लिए ईडब्ल्यूएस को 792 पद दिया गया। विचार करने वाली बात यह है कि लगभग जितनी सीट ईडब्ल्यूएस की है उसी के लगभग ओबीसी की सीटों की बेईमानी हुई है। इसकी गणितीय गणना में ईडब्ल्यूएस को मिलने वाली 792 सीटों में से ओबीसी की बेईमानी की गईं 717 सीटों को घटाया जाए तो 75 सीट ही ज्यादा है। यह इसलिए भी किया गया ताकि गणितीय गुणा गणित में सीटों का अंतर पाया जाय। ताकि यह साबित हो सके कि ओबीसी पदों की बेईमानी नहीं की गई और न ही ईडब्ल्यूएस को ओबीसी कोटे को घटाकर दिए जाने की कोई मंसा थी। यह कोई प्रशासनिक भूल नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। उद्देश्य साफ था। ओबीसी समाज के हक को छीनकर उसे ऐसे वर्ग को देना। लेकिन इस बार बेईमानी भर्ती से पहले पकड़ी गई। सिस्टम ने यह मान लिया था कि आंकड़ों की जटिलता में यह खेल दब जाएगा, लेकिन जागरूक युवाओं और सामाजिक संगठनों ने सच्चाई उजागर कर दी। सवाल यह है कि जब संविधान स्पष्ट रूप से सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण की बात करता है, तो फिर आर्थिक आधार पर बनाया गया ईडब्ल्यूएस कोटा ओबीसी के हिस्से को क्यों खा रहा है? पिछड़ों दलितों का भला करने का दावा करने वाले लोगों पिछड़े दलितों को ईडब्ल्यूएस के दायरे से बाहर क्यों रखा गया और जब ईडब्ल्यूएस के नाम पर अलग से जनरल वर्ग को आरक्षण दे दिया तो चोरी की जरूरत क्यों पड़ गई। आज स्थिति यह है कि ईडब्ल्यूएस के माध्यम से पूरे सामाजिक न्याय के ढांचे को कमजोर किया जा रहा है। यह आरक्षण की आत्मा पर हमला है। अगर आज ओबीसी की 700 से अधिक सीटें चुपचाप काटी जा सकती हैं, तो कल और भी अधिकार छीने जा सकते हैं। शायद यही सब कारण था की देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर असहमति जताई थी। यूयू ललित ने जस्टिस रविंद्र भट के राय से सहमति जताई थी कि एससी–एसटी और ओबीसी को इससे बाहर करना इस वर्ग के गरीब लोगों से भेदभाव होगा। जस्टिस एस रविंद्र भट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा था जहां तक सामाजिक न्याय की बात है तो इसमें एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को भी शामिल किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि आरक्षण के लिमिट को पार करना बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट ने अपना अल्पमत का विचार व्यक्त करते हुए ईडब्ल्यूएस आरक्षण संबंधी संविधान संशोधन पर असहमति जताई और उसे रद्द कर दिया। प्रधान न्यायाधीश ललित ने न्यायमूर्ति भट के विचार से सहमति व्यक्त की थी। यदि ईडब्ल्यूएस में यूपीएससी वर्ग को शामिल करके आरक्षण दिया गया होता तो इस तरह की बेईमानी न होती और न ही सामाजिक द्वंद पैदा होता। लेखपाल भर्ती के विज्ञापन में हुई बेईमानी का पर्दाफाश होते ही एक बार पुनः उत्तर प्रदेश की व्यापम घोटाला कहा जाने वाला 69000 भर्ती चर्चा का विषय बन गया। यह प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में लंबित है जिसकी सुनवाई आगामी चार फरवरी को होनी है। 2018 में इस भर्ती के लिए विज्ञापन आया था भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है परीक्षा के कुछ सवालों पर भी आपत्ति अभ्यर्थी द्वारा की जाती है। हालांकि उतना विवाद नहीं होता जितना की परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद बनाई गई चयन सूची पर होता है। चयन सूची में विसंगति होने के संदेह पर आरक्षित वर्ग (पिछड़ा, दलित) के अभ्यर्थियों ने पुख्ता जानकारी जुटाया और सरकार से निवेदन किया की विसंगतियों को दूर कर उन्हें नौकरी दी जाए। सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी इस मामले को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में ले गये। जांच पड़ताल के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया और उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया। रिपोर्ट के आधार पर अभ्यर्थियों ने आंदोलन शुरू किया। अभ्यर्थियों का आंदोलन पूरे प्रदेशभर में चर्चा का विषय बन गया। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस बात को स्वीकार किया की ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है।

# राशिफल

मेष :– सामाजिक गतिविधियों में आपकी क्रियाशीलता बढ़ेगी। नये लक्ष्य व कायरें में व्यस्त रहेंगे। आर्थिक क्षेत्र में परिश्रम का पूरा लाभ प्राप्त होगा। जीवन साथी के स्वास्य के प्रति सतर्कता अपेक्षित है।

बृषभ :– रोजगार में लाभकारी स्थिति मन को प्रसन्न रखेगी। सामाजिक कायरे में व्यस्त रहेंगे। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मन दुविधाग्रस्त होगा। कुछ नये संबंधों के प्रति मन उत्साहित होगा।

मिथुन :– वाक्यपटुता व व्यवहार कुशलता से संबंधों में प्रभावी होंगे। भौतिक आकांक्षाएं सार्थकता हेतु मन को उद्वेलित करेंगी। पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति हेतु मन केंद्रित होगा। परिवार में खुशहाल स्थिति रहेगी।

कर्क :– कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मन दुबिधाग्रस्त होगा। भावुकता व्यावहारिक जगत के अनुकूल चलने में बाधक बनेगी। अतरू इसे सुधारें। रोजगार में व्यस्तता रहेगी किंतु जरूरी कायरे को समय से पूर्ण करें।

सिंह :– नये उत्साह व कार्य क्षमता की अनुभूति करेंगे। कार्यक्षेत्र में अनवरत् व्यस्तता रहेगी। योजनाओं के फलीभूत होने से मन प्रसन्न होगा। महत्वपूर्ण कायरे की पूर्ति में विलम्ब कतई न करें।

कन्या :– कोई नयी इच्छा मन पर प्रभावी होगी। सामान्य दिनर्चया के साथ बीत रहे जीवन में उत्साह का अभाव रहेगा। कार्यक्षेत्र में ब्यस्तता बढ़ेगी। अपने स्वास्य के प्रति सचेत रहें।

तुला :– निराशावादी विचार योजनाओं की सार्थकता में बाधक हैं। एक साथ कई सारी चिंताओं से मन ग्रसित होगा। अभिभावको एवं श्रेष्ठजनों के सहयोग से समस्याएं हल होंगी। घर में प्रसन्नता रहेगी।

वृश्चिक :– नई प्रतिभाएं उजागर होंगी। प्रिय लोगों का सानिध्य प्राप्त होगा। शिक्षा–प्रतियोगिता में उसके परिणाम हेतु चिंतित होगा। रोजगार में स्थिति अनुकूल होगी। जीवन साथी से मधुरता कायम रखें।

धनु :– कुछ नये उत्साह व कार्य क्षमता की अनुभूति करेंगे। सभी इच्छाओं को सकार करने से पूर्व गहन सोच–विचार करें। आकस्मिक यात्रा की योजना बन सकती है।

मकर :– मर्यादा व पद का ख्याल रखते हुए अपने उच्छृंखल मन पर नियन्तण्ररखें। आकस्मिक कोई सुखद समाचार से मन प्रसन्न होगा। घर में किसी मेहमान के आगमन से व्यय संभव।

कुंभ :– महत्वपूर्ण कायरें की पूर्ति हेतु मन चिंतित होगा। प्रतिभाओं पर भरोसा रख अपने महत्वपूर्ण लक्ष्यों को फलीभूत करने हेतु केंद्रित हों। ग्रहों की अनुकूलता प्रगति के अच्छे अवसर प्रदान करेगी।

मीन :– नये कायरें के क्रियान्वयन हेतु प्रयत्न तीव्र होगा। काफी दिनों से अवरोधित कोई कार्य हल होने की संभावना है। कल्पनाओं में जीना छोड़ भौतिक जगत के अनुकूल चलने का प्रयत्न करें।

# बांग्लादेश : अस्थिरता, अराजकता और हिंसा के चक्रव्यूह में



–सुनील कुमार महला

पड़ोसी देश बांग्लादेश के हालात ठीक नहीं है और बांग्लादेश पिछले 17–18 महीनों से लगातार अस्थिरता , अराजकता और धर्मांधता की आग में झुलस रहा है। हाल ही में बांग्लादेश में फिर से हिंसा भड़क उठी, यह बहुत ही दुखद है। जानकारी के अनुसार एक छात्र नेता का शव पहुंचने के बाद ढाका में आगजनी की घटनाएं हुईं और यह दावा किया जा रहा है कि मुख्य आरोपी भारत भाग गया है तथा इधर, बॉर्डर पर भारतीय सेना अलर्ट है। गौरतलब है कि बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी का शव 19 दिसंबर 2025 शुक्रवार शाम सिंगापुर से ढाका पहुंचा और इस बीच ढाका में आंदोलनकारी फिर हिंसक हो गये। मीडिया में उपलब्ध जानकारी के अनुसार उदिची संस्था के कार्यालय को जला दिया गया। ये संस्था कट्टरपंथियों के विरोध में काम करती है। दरअसल, उदिची शिल्पी गोष्ठी बांग्लादेश का एक प्रमुख सांस्कृतिक संगठन है,जो 1968 में स्थापित हुआ था। यह प्रगतिशील कला, संगीत और रंगमंच को बढ़ावा देता रहा है। वास्तव में यह लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आजादी और मानवाधिकारों से जुड़े आंदोलनों में भी सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। हाल फिलहाल, यह बताया जा रहा है कि हत्यारों को ट्रांसपोर्टेशन में सपोर्ट करने वाले आरोपियों ने अदालत में हत्या के मुख्य आरोपी फैसल करीम के भारत भागने का दावा किया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इससे पहले उस्मान हादी की गुरुवार रात मौत हो गई थी और इसके बाद बांग्लादेश में हिंसा भड़क गई थी। इस दौरान आंदोलनकारियों ने ढाका में 2 प्रमुख मीडिया हाउस, आवामी लीग(शेख हसीना की पार्टी के ऑफिस) के कार्यालय को फूंक दिया। इतना ही नहीं, ढाका के नजदीक भालुका में धर्म का अपमान करने के आरोप में एक हिंदू युवक को पीट–पीटकर मार डाला गया।एक रिपोर्ट के मुताबिक, युवक के शव को नग्न करके एक पेड़ से लटका कर उसे आग लगा दी।मृतक की पहचान दीपू चंद्र दास के रूप में हुई है। सोशल मीडिया पर इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें लोग श्अल्लाह–हू–अकबरश के नारे लगाते दिख रहे हैं। बहरहाल, यहां यह कहना ग़लत नहीं होगा कि इन दिनों में शायद ही कोई ऐसा महीना रहा होगा, जब यहां हिंसा ना भड़की हो। सच तो यह है कि शेख हसीना की सरकार गिराने के बाद देश में शांति लाने का वादा करने वाली मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार हिंसा रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही है। हालांकि,यह बात अलग है कि यूनुस ने हाल ही की घटना पर यह बात कही है कि बांग्लादेश में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। पाठकों को बताता चलूं कि बांग्लादेश में मुहम्मद यूनुस ने शुक्रवार को छात्र नेता उस्मान की मौत के बाद भड़की हिंसक प्रदर्शनों के बीच एक हिंदू व्यक्ति की पिटाई और हत्या की कड़ी निंदा की है। यूनुस ने जोर देकर कहा कि श्नए बांग्लादेश में ऐसी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं हैश। उन्होंने कहा कि इस अपराध में शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पत्रकारों पर हमलों की भी कड़ी निंदा की है। दरअसल,उपद्रवियों ने देश के सबसे बड़े अखबार डेली स्टार और प्रोथोम आलो के ऑफिस में भी घुसकर तोड़फोड़ की थी और आग लगा दी थी। सरकार ने यह बात कही है कि वह हिंसा, धमकी, आगजनी और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की हर घटना की साफ और बिना किसी शर्त के निंदा करती है।सरकार ने कहा है कि इस समय बांग्लादेश एक ऐतिहासिक लोकतांत्रिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है, जिसे नफरत और अराजकता से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अंतरिम सरकार ने लोगों से यह अपील की है कि वे भीड़ की हिंसा का विरोध करें। सरकार ने कहा कि कुछ कट्टर और हाशिए पर मौजूद तत्व देश को अस्थिर करना चाहते हैं। क्या यह चिंताजनक बात नहीं है कि भारतीय राजनयिक परिसरों और उनके घरों पर हमले किए गए हैं तथा पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर्रहमान के आवास में भी तोड़फोड़ की गई। वास्तव में सच तो यह है कि आज भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हालात बहुत ही तेजी से बिगड़ते चले जा रहे हैं। वहां हिंसा और अराजकता बढ़ रही है और खास तौर पर हिंदुओं को निशाना बनाए जाने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इसी बीच एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें पुराने श्सिराजुद्दौला साम्राज्यश को दोबारा बनाने की बात कही जा रही है, जिसमें भारत के कुछ हिस्सों को भी शामिल बताया गया है। वास्तव में,इससे माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया है। बांग्लादेश में इन घटनाओं ने यह सवाल खड़े कर दिये हैं कि बांग्लादेश क्या सांप्रदायिक उग्रता की ओर बढ़ रहा है या फिर उसे जानबूझकर अस्थिर किया जा रहा है। भारत की चिंता यह भी है कि मौजूदा बांग्लादेशी नेतृत्व की नीतियां, बांग्लादेश में पाकिस्तान जैसी सोच को ही बढ़ावा दे रही हैं, जिससे भारत–विरोधी ताकतों को वहां खुला मंच मिल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद अली जिन्ना की विचारधारा पर चल रहे हैं। यहां पाठकों को बताता चलूं कि 1920 से पहले जिस जिन्ना को शहिंदू–मुस्लिम एकता का राजदूतश कहा जाता था, 1920 के बाद राजनीतिक परिस्थितियों के बदलने, कांग्रेस के बढ़ते वर्चस्व और मुस्लिम समुदाय के भविष्य को लेकर आशंकाओं के कारण उनकी सोच में परिवर्तन आ गया था और वे मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और संवैधानिक सुरक्षा पर जोर देने लगे थे। 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद जिन्ना इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि हिंदू और मुस्लिम केवल धार्मिक नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी अलग राष्ट्र हैं, और इसी विचार से द्विराष्ट्र सिद्धांत तथा पाकिस्तान की मांग सामने आई थी। बहरहाल, भारतीय संसद की विदेश मामलों की समिति ने भी अपनी एक रिपोर्ट में यह बात कही है कि 1971 के बाद यह भारत के लिए बांग्लादेश से जुड़ा सबसे बड़ा कूटनीतिक और रणनीतिक संकट है। समिति के अनुसार, बांग्लादेश में चल रही हिंसा से भारत को गंभीर सुरक्षा और कूटनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।इसके साथ ही, भारत को यह डर भी है कि बांग्लादेश चीन के और करीब जा सकता है, जैसा कि चीन ने मोंगला बंदरगाह के विस्तार में भारी निवेश किया है। यहां पाठकों को बताता चलूं कि मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है तथा यह देश के दक्षिण–पश्चिमी हिस्से में, पशुर नदी के तट पर स्थित है और सुंदरबन के निकट होने के कारण रणनीतिक व पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसकी स्थापना 1950 के दशक में हुई थी।इस बंदरगाह से भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए वहां रेलवे परियोजना में निवेश किया है। अंत में यही कहूंगा कि बांग्लादेश की स्थिति अब सिर्फ विदेश नीति की ही समस्या नहीं रही है, बल्कि यह भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी एक खतरा बनती जा रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो बांग्लादेश में हालिया राजनीतिक–सामाजिक अस्थिरता ने भारत के लिए कहीं न कहीं गंभीर चिंता का विषय है। वहां बढ़ते विरोध–प्रदर्शन, हिंसा और भारत–विरोधी माहौल का असर सीमा सुरक्षा, द्विपक्षीय व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ रहा है। पिछले कुछ समय से भारत ने सीमावर्ती क्षेत्रों में और अधिक सतर्कता बढ़ाई है, क्योंकि अस्थिरता से अवैध गतिविधियों, शरणार्थी दबाव और बाहरी शक्तियों के प्रभाव की आशंका रहती है। कुल मिलाकर, बांग्लादेश का संकट भारत के लिए केवल पड़ोसी देश की समस्या नहीं, बल्कि सुरक्षा, कूटनीति और भू–राजनीतिक हितों से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है।ऐसे हालात में भारत को बहुत सतर्क और समझदारी से कदम उठाने की जरूरत है।

# पर्यावरण संकट : नीतियों से नहीं, नागरिक चेतना से बचेगी प्रकृति

## सरकारों की विफलता के साथ–साथ हमारी जीवन–शैली भी पर्यावरण विनाश की सबसे बड़ी ज़िम्मेदार है



–डॉ. प्रियंका सौरभ

पर्यावरण संरक्षण की बहस अक्सर एक सुविधाजनक दिशा में मोड़ दी जाती हैकृसरकारें नीतियाँ नहीं बनातीं, मंत्रालय निष्क्रिय हैं, क़ानून काग़ज़ों तक सीमित हैं। यह आलोचना पूरी तरह ग़लत नहीं है। केंद्रीय और राज्य स्तर पर पर्यावरण मंत्रालयों का रिकॉर्ड देखें तो विकास परियोजनाओं के सामने प्रकृति अक्सर सबसे पहले बलि चढ़ती दिखती है। जंगलों की कटाई, नदियों का प्रदूषण, ज़हरीली हवा और भूजल का संकटकृ इन सबके लिए नीतिगत विफलता ज़िम्मेदार है। पर यह अधूरा सच है। पूरा सच यह है कि पर्यावरण संकट की जड़ें हमारी अपनी जीवन–शैली में गहरी धँसी हुई हैं। हमने पर्यावरण को सरकार का विषय मान लिया है, जैसे वह नागरिक जीवन से अलग कोई विभागीय फाइल हो। यह मानसिकता ही सबसे बड़ा संकट है। हवा, पानी, मिट्टी और जंगल किसी मंत्रालय की संपत्ति नहीं, बल्कि सामूहिक उत्तरदायित्व हैं। जब नागरिक स्वयं को इस उत्तरदायित्व से अलग कर लेता है, तब कोई भी नीति प्रभावी नहीं रह जाती। आज प्रदूषण का बड़ा हिस्सा किसी कारख़ाने से नहीं, बल्कि रोज़मर्रा के घरेलू व्यवहार से पैदा हो रहा हैकृ अत्यधिक निजी वाहन, बेहिसाब प्लास्टिक, अनियंत्रित कचरा, पानी और बिजली की फिजूलखर्ची। हम सुविधाओं को अधिकार मानते हैं और उनके दुष्परिणामों को व्यवस्था की समस्या। यही सोच पर्यावरण को धीरे–धीरे बर्बादी की ओर धकेल रही है। भारत जैसे विकासशील देश में पर्यावरण संरक्षण को अक्सर विकास विरोधी बताकर खारिज कर दिया जाता है। यह एक कृत्रिम और भ्रामक बहस है। सच्चाई यह है कि प्रकृति का विनाश स्वयं विकास के ख़िलाफ़ है। बाढ़, सूखा, गर्मी की चरम लहरें, जल संकट और बीमारियाँकृये सब उसी "विकास" की देन हैं, जो प्रकृति के संतुलन को नज़रअंदाज़ करता है। लेकिन इस बहस में भी नागरिक की भूमिका गौण बना दी जाती है। हम यह नहीं पूछते कि हमारे विकास के मॉडल में हमारी व्यक्तिगत आदतें कितनी ज़िम्मेदार हैं। क्या हर छोटी दूरी के लिए कार निकालना ज़रूरी है? क्या हर शादी, समारोह और त्योहार में अनावश्यक दिखावा आवश्यक है? क्या एकल–उपयोग प्लास्टिक के बिना जीवन असंभव है? इन सवालों से हम बचते हैं, क्योंकि इनके जवाब हमें असहज करते हैं। पर्यावरण संरक्षण केवल क़ानूनों और नियमों से संभव नहीं। यह नागरिक चरित्र और सामाजिक संस्कार का प्रश्न है। जिन देशों में पर्यावरणीय अनुशासन दिखाई देता है, वहाँ केवल सख़्त क़ानून नहीं, बल्कि नागरिकों की आदतें भी अनुशासित हैं। भारत में समस्या यह है कि हम अधिकारों को लेकर अत्यंत सजग हैं, पर कर्तव्यों को लेकर लगभग उदासीन। हम अपने घर के बाहर गंदगी फैलाने में संकोच नहीं करते, पर स्वच्छता की अपेक्षा सरकार से करते हैं। हम नदियों को पूजा के नाम पर प्रदूषित करते हैं, फिर उनकी सफ़ाई के लिए आंदोलन करते हैं। यह विरोधाभास हमारी सामाजिक मानसिकता को उजागर करता है। पेड़ लगाने की बात आए तो उत्साह केवल सरकारी अभियानों और फोटो अवसरों तक सीमित रह जाता है। वृक्षारोपण दिवस पर पौधे लगाए जाते हैं और अगले दिन भुला दिए जाते हैं। संरक्षण की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। यही कारण है कि आँकड़ों में लाखों पौधे लगते हैं, पर धरातल पर जंगल घटते जाते हैं। एक पुरानी कहावत हैकृमनुष्य जीवन भर नौ मन लकड़ी लेकर जाता है, तो कम से कम अपने पीछे नौ मन पेड़ छोड़ जाना चाहिए। यह कहावत आज के समय में कहीं अधिक प्रासंगिक है। हम अपने जीवन में जितने संसाधन उपभोग करते हैं, क्या उनके बराबर कुछ लौटाने का प्रयास करते हैं? आज पेड़ लगाना कोई महान कार्य नहीं रहा, बल्कि एक न्यूनतम नैतिक दायित्व बन चुका है। इसके बावजूद हम इसे टालते हैं। जगह, समय, पानी और देखभालकृहर चीज़ का बहाना हमारे पास है। सच्चाई यह है कि हमने सुविधा को प्राथमिकता और ज़िम्मेदारी को बोझ मान लिया है। पेड़ न लगाना केवल पर्यावरणीय लापरवाही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के जीवन के साथ अन्याय है। यह एक ऐसा अपराध है, जिसकी सज़ा हमारे बच्चे चुकाएँगेकृगंदी हवा, जहरीला पानी और असुरक्षित भविष्य के रूप में। यह कहना भी सही नहीं होगा कि सरकारों की कोई भूमिका नहीं है। पर्यावरणीय क़ानूनों का सख़्ती से पालन, परियोजनाओं का ईमानदार पर्यावरणीय आकलन, प्रदूषकों पर कठोर दंड और स्थानीय निकायों को सशक्त करनाकृये सब अनिवार्य हैं। पर इतिहास गवाह है कि जब समाज निष्क्रिय हो, तब सबसे अच्छे क़ानून भी निष्प्रभावी हो जाते हैं। स्वच्छ भारत अभियान इसका उदाहरण है। जहाँ नागरिकों ने भागीदारी दिखाई, वहाँ परिणाम दिखे। जहाँ इसे केवल सरकारी योजना समझा गया, वहाँ स्थिति जस की तस रही। पर्यावरण संरक्षण भी इसी सिद्धांत पर काम करेगा। पर्यावरण संकट का समाधान किसी एक बड़े निर्णय में नहीं, बल्कि लाखों छोटे नागरिक निर्णयों में छिपा है। घर–घर कचरा पृथक्करण, वर्षा जल संचयन, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, ऊर्जा–सक्षम उपकरण, स्थानीय स्तर पर वृक्षारोपणकृये सभी कदम साधारण हैं, पर प्रभावशाली हैं। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित न रखकर व्यवहार में उतारना होगा। बच्चों को प्रकृति से जोड़ना होगा, ताकि वे केवल जानकारी नहीं, संवेदना भी विकसित करें। मीडिया और सामाजिक संगठनों की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण है। पर्यावरण को केवल आपदा या दिवस के रूप में नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की चिंता के रूप में प्रस्तुत करना होगा। अंततः पर्यावरण संकट का सबसे ईमानदार उत्तर हमें स्वयं से पूछना होगाकृहम प्रकृति को क्या दे रहे हैं? जब तक यह प्रश्न हर नागरिक के मन में नहीं उठेगा, तब तक नीतियाँ आती–जाती रहेंगी और प्रकृति चुपचाप नष्ट होती रहेगी। प्रकृति किसी मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं, यह हमारे सामूहिक चरित्र की परीक्षा है। और इस परीक्षा में अब तक हम असफल ही रहे हैं। अब भी समय हैकृयदि हम सच में विकास चाहते हैं, तो उसे प्रकृति के साथ सामंजस्य में गढ़ना होगा, वरना आने वाली पीढ़ियाँ हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी।

# जल का विस्मरण : आधुनिकता, अहंकार और सूखती हुई धरती



–डॉ सत्यवान सौरभ

भारत के समकालीन संकटों में जल सबसे अधिक चर्चित है, पर सबसे कम समझा गया भी। सूखा, बाढ़, गिरता भूजल, प्रदूषित नदियाँकृइन सबको हम अलग–अलग घटनाओं की तरह देखते हैं, जबकि ये एक ही कहानी के अलग अध्याय हैं। यह कहानी प्राकृतिक आपदा की नहीं, बल्कि मानवीय विस्मृति की है। हमने जल को केवल संसाधन समझ लिया और उसके साथ जुड़ी स्मृति, संस्कार और संवेदना को त्याग दिया। बाँध बनाकर पानी को ज़मीन के ऊपर रोकने का विचार आधुनिक विकास की सबसे बड़ी भ्रांतियों में से एक है। यह व्यवस्था प्रकृति के स्वभाव के विरुद्ध खड़ी की गई है। जल का स्वभाव ठहरना नहीं, उतरना हैकृधरती की कोख में समाना, वहाँ से जीवन को पोषित करना। तालाब, जोहड़, कुएँ और बावड़ियाँ इसी स्वभाव की अभिव्यक्ति थे। वे पानी को रोकते नहीं थे, सहेजते थे। यही कारण है कि वे समय–सिद्ध और स्वयं–सिद्ध व्यवस्थाएँ थीं, जिन्होंने लाखों वर्षों तक मानव सभ्यता का साथ दिया। आज हम बाँधों को विकास का प्रतीक मानते हैं, जबकि तालाबों को पिछड़ेपन की निशानी समझते हैं। यह दृष्टि का पतन है। एक समय पंजाब में सत्रह हज़ार से अधिक तालाबों का उल्लेख मिलता है। वे केवल जलस्रोत नहीं थे, बल्कि सामुदायिक जीवन के केंद्र थेकृपशुओं, खेतों, पक्षियों और मनुष्यों को जोड़ने वाले जीवित स्थल। आज स्थिति यह है कि तालाब तो दूर, पंजाब में शामलात ज़मीनों तक का समुचित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं। जब स्मृति मिटा दी जाती है, तो संकट अपरिहार्य हो जाता है।

हमारे पुरखे जानते थे कि बाढ़ विनाश नहीं, अवसर है। वे जानते थे कि यदि बाढ़ का पानी फैलकर तालाबों, जोहड़ों और मैदानों में उतरे, तो वही पानी धरती को पुनर्जीवित करेगा। इसलिए तालाबों से मिट्टी निकालने की परंपराएँ थींकृकोई इसे श्रमदान कहता था, कोई सामाजिक कर्तव्य। तालाब गहरे होते थे, उनकी कोख विस्तृत होती थी और वे वर्षा के अधिकतम जल को आत्मसात कर लेते थे। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें तकनीक नहीं, समझ काम करती थी। विडंबना यह है कि जिन हाथों ने तालाबों को पाटा, जोहड़ों को भर दिया और कुओं को कचरे से बंद कर दिया, वही हाथ आज पानी के लिए आसमान की ओर देख रहे हैं। तालाबों को मारने वाले जब स्वयं मरने लगते हैं, तो दोष प्रकृति पर, जलवायु परिवर्तन पर या पूर्वजों पर मढ़ दिया जाता है। आत्मालोचना का साहस अब दुर्लभ होता जा रहा है। यह संकट केवल जल का नहीं, शिक्षा का भी है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि ठीक से शिक्षित होने का अर्थ क्या है। क्या यह केवल डिग्रियाँ, आंकड़े और तकनीकी शब्दावली है? नहीं। ठीक से शिक्षित होने का अर्थ है सामवेदी होनाकृभगवत्ता द्वारा प्रदत्त पूरे इकोसिस्टम से एकात्म होना। जब मनुष्य स्वयं को प्रकृति से अलग मानने लगता है, तब उसका ज्ञान चतुराई बन जाता है और चतुराई अंततः विनाश की ओर ले जाती है। शेष सब तो बकलोली के ही परिष्कृत रूप हैं। देश में जल–प्रबंधन की स्थिति का अंदाज़ा इसी एक तथ्य से लगाया जा सकता है कि आज तक ऐसा कोई विस्तृत, विश्वसनीय और समग्र सर्वेक्षण नहीं हो सका है, जिससे यह पता चले कि भारत में वास्तव में कुल जल कितना है। हम योजनाएँ बनाते हैं, बजट स्वीकृत करते हैं और घोषणाएँ करते हैं–बिना यह जाने कि आधार क्या है। यह नीति नहीं, अनुमान है; और अनुमान पर खड़ा विकास देर–सवेर ढहता ही है। भूजल–दोहन की तस्वीर तो और भी भयावह है। पंजाब में लगभग साढ़े सत्रह लाख और हरियाणा में लगभग नौ लाख सबमर्सिबल धरती के गर्भ से पानी उलीच रहे हैं। धरती मानो सबमर्सिबलों की शर–शय्या पर लेट चुकी है। बिना किसी इच्छा–मृत्यु के वरदान के, हम उसे प्रतिदिन थोड़ा–थोड़ा मार रहे हैं। यह हरियाली की कीमत पर रची गई एक मौन त्रासदी है, जो आने वाले समय में विकराल रूप धारण करेगी। पर्यावरण की कीमत पर होने वाला विकास उसी डाल पर बैठने जैसा है, जिसे हम स्वयं काट रहे हैं। यह स्थिति कालिदास की कथा की याद दिलाती हैकृजहाँ मूर्खता को विद्वत्ता का आवरण ओढ़ा दिया जाता है। चौड़ी सड़कें, ऊँची इमारतें और चमकदार परियोजनाएँ हमें प्रगति का भ्रम देती हैं, जबकि भीतर से ज़मीन सूख रही होती है। यह विकास नहीं, सजाया हुआ विनाश है। शहर इस विफलता के सबसे स्पष्ट उदाहरण हैं। आधुनिक विद्या–केन्द्रों और नीति–निर्माताओं के पास आज भी कोई समग्र दृष्टि नहीं है, जिसके अनुसार भारतीय शहरों में जल–निकासी, जल–संरक्षण, गंदगी के उत्पादन में कमी और उत्पन्न गंदगी के उपयोग का कोई राष्ट्रीय ढाँचा हो। बारिश में शहर डूबते हैं और गर्मियों में वही शहर प्यास से कराहते हैं। यह विरोधाभास व्यवस्था की नहीं, दृष्टि की असफलता का प्रमाण है। नदियों की हालत इस कहानी का सबसे मार्मिक अध्याय है। प्रदूषित नदियों की सूची इतनी लंबी हो चुकी है कि उसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो हम किसी मृतकों की नामावली देख रहे हों। जिन नदियों ने सभ्यताओं को जन्म दिया, आज वे हमारी लापरवाही की शिकार हैं। हम उन्हें माँ कहते हैं, पर व्यवहार ऐसा करते हैं मानो वे अनंत सहनशील हों। यह सांस्कृतिक पाखंड अब अपनी सीमा पर पहुँच चुका है। अभी कुछ ही दशक पहले तक भारत के शहर, गाँव, चरागाहें, खेत, जंगल, तालाब, कुएँ और बावड़ियाँ जीवन से भरे हुए थे। यह कोई आदर्शीकृत अतीत नहीं, बल्कि सामाजिक स्मृति का तथ्य है। उस समय संसाधन सीमित थे, पर समझ व्यापक थी। समुदाय था, सहभागिता थी और प्रकृति के साथ सहजीवन का भाव था। सरकारी विकास कार्यक्रमों ने इस सामाजिक चरित्र को छिन्न–भिन्न कर दिया। योजनाएँ बढ़ीं, पर समाज सिकुड़ गया। आज आवश्यकता इस बात की है कि जल–प्रबंधन को केवल इंजीनियरों और योजनाकारों के हवाले न छोड़ा जाए। यह प्रश्न तकनीकी से अधिक नैतिक और सांस्कृतिक है। तालाबों का पुनर्जीवन, जोहड़ों की वापसी, वर्षा–जल संचयन और सामुदायिक भूमि की रक्षाकृये सब भविष्य की खोज नहीं, अतीत की स्मृति हैं। हमें पीछे लौटना नहीं, बल्कि याद करना है। जल कोई वस्तु नहीं, एक संबंध हैकृ मनुष्य और प्रकृति के बीच। जब यह संबंध टूटता है, तो आपदाएँ जन्म लेती हैं। समय अभी भी है, पर चेतावनी स्पष्ट है। यदि हमने जल के साथ अपना रिश्ता नहीं सुधारा, तो इतिहास हमें उस पीढ़ी के रूप में याद रखेगा, जिसने अपनी ही धरती को प्यास से मार दिया।

## एडवोकेट अमर बहादुर अरावली को मृत्युदंड

पर्यावरण संरक्षण का मोदी सरकार का वादा उसके बाकी वादों की तरह न केवल खोखला है, बल्कि डरावना भी है। इस संरक्षण के नाम पर सरकार ने एक उद्योगपति को निजी जंगल बनाकर उसमें तमाम तरह के जानवर पालने की अनुमति दे दी। पूरी दुनिया में ऐसे भ्रष्टाचार की मिसाल नहीं मिलेगी। लेकिन पर्यावरण को लेकर सरकार के खौफनाक रवैये का यह अकेला उदाहरण नहीं है। नया उदाहरण 2 अरब साल पुरानी अरावली पर्वत श्रृंखला को सुप्रीम कोर्ट के जरिए मृत्युदंड सुनाने का है। सरकार की बनाई कमेटी की तय परिभाषा के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अरावली में खनन की जो अनुमति दी है, वह किसी मृत्युदंड से कम नहीं है।अगड़े–पिछड़े, लोकतांत्रिक –तानाशाही वाले तमाम देशों में पर्यावरण के मुद्दों पर व्यापक बहस होती है, फिर भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखकर फैसले लिए जाते हैं। लेकिन भारत शायद इकलौता देश है जहां सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर केंद्र की सिफारिश पर अपनी मुहर लगा दी और इसमें पर्यावरणविदों की राय जरूरी नहीं समझी गई। सरकार ने किसी पर्यावरणविद को भले सलाहकार नहीं बनाया, फिर भी अरावली में खनन के खिलाफ जो आवाजें चारों तरफ से उठ रही हैं।

# प्रेरणा स्थल कार्यक्रम व स्वच्छ सर्वेक्षण के मद्देनज़र नगर आयुक्त का शहर के विभिन्न जोनों में निरीक्षण

## - हवाईअड्डे से प्रेरणा स्थल तक व्यवस्थाओं का लिया जायजा, सौंदर्यकरण व स्वच्छता पर दिए सख्त निर्देश

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। नगर आयुक्त श्री गौरव कुमार ने सोमवार को नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शहर के विभिन्न जोनों में व्यापक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण 25 दिसंबर को प्रेरणा स्थल पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम तथा स्वच्छ सर्वेक्षण 2025–26 की तैयारियों के दृष्टिगत किया गया। निरीक्षण का उद्देश्य शहर की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना और आमजन एवं आगंतुकों को स्वच्छ, सुव्यवस्थित व सुंदर वातावरण उपलब्ध कराना रहा।

नगर आयुक्त ने चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से प्रेरणा स्थल तक पड़ने वाले प्रमुख मार्गों, चौराहों और स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सडकों की स्थिति, डिवाइडरों, फुटपाथों, नालियों, हरित पट्टियों तथा सार्वजनिक स्थलों की साफ–सफाई का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी कमियों को दूर किया जाए।

निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने मार्गप्रकाश व्यवस्था को दुरुस्त रखने, खराब स्ट्रीट लाइटों को तत्काल ठीक कराने तथा अंधेरे स्थानों पर अतिरिक्त प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सौंदर्यकरण के कार्यों पर विशेष ध्यान देने को कहा, जिसमें पेंटिंग, पौधारोपण, साज–सज्जा एवं अव्यवस्थित सामग्री को हटाने के निर्देश शामिल रहे।

स्वच्छता को लेकर नगर आयुक्त ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि प्रमुख मार्गों और कार्यक्रम स्थल के आसपास नियमित सफाई, कूड़ा उठान की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025–26 को ध्यान में रखते हुए सभी जोनों में निरंतर निगरानी रखी जाए और लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इस निरीक्षण के दौरान अपर नगर आयुक्त, मुख्य अभियंता, जलकल महाप्रबंधक, समस्त अधिशासी अभियंता सहित नगर निगम के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। नगर आयुक्त ने सभी अधिकारियों से समन्वय बनाकर कार्य करने का आह्वान किया और कहा कि निर्धारित कार्यक्रम एवं स्वच्छता मानकों को समय रहते पूरा किया जाना नगर निगम की प्राथमिकता है।

# लिटिल मिलेनियम स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने डांस कर जीता अभिभावकों का दिल

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। (हरिओम मिश्रा) राजधानी में विराजखण्ड स्थित लिटिल मिलेनियम स्कूल ने तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम के आलावा छोटे –छोटे बच्चों के डांस के साथ अपना एनुअल डे बड़ी धूमधाम से मनाया। छोटे बच्चों ने झूम –झूम कर मतवाली मस्ती में डांस कर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम का शुभारम्भ मुख्य अतिथि राजीव कुमार पांडेय जी (प्रिंसिपल ,DAV स्कूल )एवं डॉक्टर सुधाकर मिश्र (RETD CMO )के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। सरस्वती वंदना ,पंजाबी डांस,संभा डांस ,हनुमान चालीसा जैसे कई कार्यक्रमों ने सभी का दिल जीत लिया.

लिटिल मिलेनियम स्कूल की प्रिंसिपल ने बताया कि हर वर्ष की तरह ही इस बार भी स्कूल प्रवंधन ने एनुअल डे मनाने का संकल्प लिया था जिसे आज पूरा किया गया। उन्होंने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम की वजह से स्कूल प्रवंधन ,टीचर्स ,बच्चो और अभिभावकों के साथ एक आपसी तालमेल और लगाव जैसा संबंध बन जाता है और बच्चों में कार्यक्रम में प्रतिभाग करने से कॉन्फिडेंस आता है।प्रिंसिपल ने इस खास कार्यक्रम में आये सभी आगंतुकों,अभिभावकों और बच्चो का आभार व्यक्त किया।

# यूपी विधान परिषद में पुनर्नियोजित चिकित्सकों की आयु सीमा बढ़ाने की मांग

संवाददाता

लखनऊ। शीतकालीन सत्र के दौरान सोमवार को उत्तर प्रदेश विधान परिषद में शून्यकाल के दौरान विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक ने नियम–111 के अंतर्गत प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ से जुड़े पुनर्नियोजित चिकित्सकों की आयु सीमा बढ़ाने की मांग को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने सदन में कहा कि पुनर्नियोजित चिकित्सकों की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष किए जाने से प्रदेश में चिकित्सकों की कमी दूर होगी और राज्य चिकित्सा सेवा को और अधिक गतिमान बनाने में सहायता मिलेगी। सदस्य ने कहा कि योगी सरकार राज्य के प्रत्येक नागरिक को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल कॉलेज जैसी योजनाओं के साथ–साथ अस्पतालों के उच्चीकरण का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है, जिससे चिकित्सकों की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। विजय बहादुर पाठक ने कहा कि सरकार ने चिकित्सकों की सेवा आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है, लेकिन पुनर्नियोजित चिकित्सकों की आयु सीमा अब भी 62 से 65 वर्ष के बीच निर्धारित है। आयोग से नए विशेषज्ञ चिकित्सकों की सीमित उपलब्धता के कारण प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी बनी हुई है। ऐसे में सेवानिवृत्त चिकित्सकों के पुनर्नियोजन की आयु सीमा 70 वर्ष किए जाने से यह समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि मेडिकल कॉलेजों में पहले ही पुनर्नियोजित चिकित्सकों की तैनाती की आयु सीमा 70 वर्ष कर दी गई है।

जब यह सुविधा मेडिकल कॉलेजों में दी जा सकती है, तो राज्य के अन्य चिकित्सा संस्थानों और सेवाओं में भी इसे लागू किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार की सीजीएचएस, राज्य सरकार के बीमा चिकित्सालयों और चिकित्सा शिक्षा विभाग में भी 70 वर्ष तक पुनर्नियोजन के उदाहरण मौजूद हैं। इसके साथ ही शून्यकाल में विधान परिषद सदस्य ने राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर पर गठित निगरानी समितियों की अनियमित बैठकों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि दिशा की तर्ज पर राज्य योजनाओं की समीक्षा के लिए गठित इन समितियों की कुछ जनपदों में बैठकें हुई हैं, लेकिन अधिकांश जिलों में अब तक नियमित बैठकें नहीं हो पाई हैं। उन्होंने इन समितियों की बैठकों को नियमित रूप से आयोजित कराने की मांग की। सभापति की व्यवस्था के बाद सदन के नेता ने इस विषय पर सदन को आश्वस्त किया कि निगरानी समितियों की बैठकों को नियमित कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

# अनुपूरक बजट इस बात का प्रमाण है कि सरकार की नीतियां जमीनी जरूरतों से कटी हुई हैं : लोकदल

संवाददाता

लखनऊ। लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह जी ने अन्नपूरक बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहां है कि यह अनुपूरक बजट किसानों के लिए नहीं, बल्कि घोषणाओं और फाइलों के लिए है। किसान आज भी खाद, बिजली, पानी, भुगतान और इलाज के लिए भटक रहा है। 24,496.98 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश कर सरकार आंकड़ों का ढोल पीट रही है, लेकिन जमीन पर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। 8. 08 लाख करोड़ के मूल बजट के बावजूद आज सरकार को फिर अनुपूरक बजट लाना पड़ रहा है, यह स्वयं स्वीकारोक्ति है कि योजनाएं सही तरीके से बनी ही नहीं। सरकार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पावर, हेल्थ, नगर विकास, महिला–बाल कल्याण और गन्ना किसानों के नाम पर बड़े–बड़े दावे कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि, क्या किसानों को आज भी खाद, बिजली और गन्ना भुगतान समय पर मिल रहा है? क्या सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर, दवाएं और इलाज की व्यवस्था सुधरी है? क्या नगर विकास के नाम पर शहरों की बदहाल सड़कों, जलभराव और गंदगी से निजात मिली है? क्या महिला और बाल कल्याण केवल बजट पुस्तिका तक सीमित नहीं रह गया है? अनुपूरक बजट इस बात का प्रमाण है कि सरकार की नीतियां जमीनी जरूरतों से कटी हुई हैं। जब तक बजट का लाभ आखिरी व्यक्ति, किसान, मजदूर, महिला और युवा तक नहीं पहुंचेगा, तब तक ऐसे बजट केवल कागजी अभ्यास बनकर रहेंगे। सरकार को नए बजट लाने से पहले पुराने बजट के खर्च और उसके परिणामों पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। जनता अब आंकड़ों से नहीं, जवाबदेही से शासन का मूल्यांकन करेगी।

# कैसरबाग में सिल्क परिधानों की भव्य प्रदर्शनी का शुभारंभ

संवाददाता

लखनऊ। क्रिसमस और नववर्ष के शुभ अवसर पर कैसरबाग स्थित ऐतिहासिक सफेद बारादरी में विभिन्न राज्यों के बुनकरों द्वारा तैयार किए गए सिल्क परिधानों की विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया । इस प्रदर्शनी का आयोजन न्यू क्राफ्ट सिल्क इंडिया संस्था द्वारा किया गया 4 जनवरी 25 तक चलने वाले एक्सपो भारतीय हैंडलूम संस्कृति और प्रकृति–सम्मत परिधानों का अनोखा संगम है। प्रदर्शनी में बनारसी, चंदेरी, तस्सर, कांचीपुरम, इक्कत, पैठानी, जयपुरी बगरू प्रिंट जैसे परिधान और सिल्कहैंडलूम मार्क वाले शुद्ध प्राकृतिक रेशों के उत्पाद मुख्य आकर्षण रहे। प्रदर्शनी का उद्घाटन सोमवार फैशन क्रियेटर व मॉडल दिव्या ध्रूबी ने किया प्रदर्शनी में एम टीवी स्टार मोनिस सेविटार भी मौजूद रहे। देश के अलग–अलग राज्यों से आए बुनकरों के उत्कृष्ट सिल्क वस्त्र प्रदर्शित किए जाएंगे, जो पारंपरिक शिल्प और आधुनिक डिजाइन का अनूठा संगम होंगे।

# लुलु हाइपरमार्केट द्वारा आयोजित फूड फिएस्टा 2025 का भव्य समापन, गोल्डी द्वारा प्रायोजित सुपर शेफ प्रतियोगिता के साथ सम्पन्न हुआ

संवाददाता

लखनऊ। गोल्डी द्वारा प्रायोजित लुलु सुपर शेफ के साथ आशीर्वाद प्रस्तुत लुलु फूड फिएस्टा 2025, जिसे सनफीस्ट द्वारा पावर किया गया तथा चकदे, पिटारा, एवा और टाटा सोलफुल के सहयोग से आयोजित किया गया, अपने आखिरी दिन एक जबरदस्त और रोमांचक कुकिंग प्रतियोगिता के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस भव्य आयोजन ने खाने और पाक–कला के शौकीनों के लिए एक शानदार मंच प्रदान किया। फूड फिएस्टा के अंतिम दिन प्रतिभागियों के बीच लाइव कुकिंग सेशन आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने अपनी रचनात्मकता, स्वाद और प्रस्तुति से जजों व दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कड़े मुकाबले के बाद विजेताओं की घोषणा की गई, जिन्हें आकर्षक नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रतियोगिता के विजेता इस प्रकार रहेरू मानसी गुप्ता दृ विजेता (50,000–) नीलिमा शर्मा दृ प्रथम रनर–अप (30,000–) सानिया जेहरादृ द्वितीय रनर–अप (20,000–) इस प्रतियोगिता में ताज ग्रुप ऑफ होटल्स के प्रतिष्ठित शेफ, संजय अग्रवाल ने जूरी जज की भूमिका निभाई। उनके अनुभव और विशेषज्ञता ने प्रतियोगिता को और भी खास बना दिया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुनील शर्मा, जनरल मैनेजर, लुलु हाइपरमार्केट ने कहा, "लुलु हाइपरमार्केट हमेशा अपने ग्राहकों और ग्राहकों को ऐसे मंच उपलब्ध कराने का प्रयास करता है, जहाँ वे अपनी प्रतिभा और पाक–कला कौशल को प्रदर्शित कर सकें।" शानदार प्रतिस्पर्धा, स्वाद से भरपूर व्यंजन और उत्साह से भरे माहौल के साथ लुलु फूड फिएस्टा 2025 की शानदार समाप्ति हुई।

# जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए 1,246 करोड़ का प्रावधान

## भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को दी जाएगी रफ्तार

## नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से किया जा रहा है लिंक

## गंगा एक्सप्रेसवे के लिये1,835 करोड़ व गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 100 करोड़ का प्रावधान

संवाददाता

लखनऊ। योगी सरकार ने औद्योगिक विकास और वैश्विक कनेक्टिविटी को नई गति देने के लिए जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे तक प्रवेश–नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 1,246 करोड़ रूपये की धनराशि का प्रावधान अनुपूरक बजट में किया है। इस धनराशि के माध्यम से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। परियोजना उत्तर प्रदेश को अंतरराष्ट्रीय निवेश, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक विस्तार के वैश्विक मानचित्र पर और मजबूत करने की दिशा में एक निर्णायक कदम मानी जा रही है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के माध्यम से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर को सीधे गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा रहा है, जिससे माल परिवहन, निर्यात, औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला और यात्री आवागमन को निर्बाध गति मिलेगी। सरकार का मानना है कि यह कॉरिडोर प्रदेश में निवेश आकर्षण, रोजगार सृजन और औद्योगिक क्लस्टर्स के विकास को अभूतपूर्व बढ़ावा देगा।अनुपूरक बजट में औद्योगिक और अवस्थापना विकास को व्यापक समर्थन देते हुए गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए बीजीएफ के अंतर्गत 1,835 करोड़ तथा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस प्रस्तावित धनराशि के माध्यम से एक्सप्रेसवेज के विकास में आ रही बाधाओं को दूर किया जाएगा। आगरालखनऊ एक्सप्रेसवे के 292 किलोमीटर हिस्से में बाईं ओर नए जन सुविधा परिसर एवं वाहन पार्किंग स्थलों के निर्माण के लिए 5 लाख की प्रतीक मांग रखी गई है, जिसे अनुदानों में होने वाली बचत से वहन किया जाएगा।औद्योगिक निवेश को गति देने के लिए सरकार ने विभिन्न निवेश प्रोत्साहन नीतियों के अंतर्गत भी भारी धनराशि प्रस्तावित की है। त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 के कार्यान्वयन हेतु 75 करोड़, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एवं फॉर्च्यून–500 कंपनियों के निवेश प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत 371. 69 करोड़, उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 के अंतर्गत 23.03 करोड़ रूप तथा औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत 823.43 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए धनराशि प्रस्तावित की गई है। इसके अलावा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास नीति 2012 के लिए 100 करोड़ और औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के लिए 300 रूपये करोड़ का प्रावधान किया गया है।लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन को सुदृढ़ करने के लिए जिला उद्योग केंद्र के अधिष्ठान व्यय के लिए 1.5 करोड़ और उद्योग निदेशालय के अधिष्ठान व्यय के लिए भी 1.5 करोड़ की व्यवस्था की गई है। हथकरघा क्षेत्र में पीएम मित्र पार्क के संचालन के लिए वृक्ष पातन एवं प्रतिपूरक वृक्षारोपण शुल्क के भुगतान के लिए 85 रूपये करोड़ का प्रावधान किया गया है।

# महंत पंडित विनोदानंद शास्त्री जी महाराज के अनुसार ईश्वर की करुणा से कोई अछूता नहीं है

संवाददाता

लखनऊ। एकादश श्रीमद् भागवत कथा, कमता महोत्सव एवं 21 कुंडीय ज्ञान यज्ञ एवं भण्डारे का आयोजन 25 दिसम्बर तक कमता स्थित शंकरपुरी कालोनी में किया जा रहा है। इसमें महंत पंडित विनोदानंद शास्त्री जी महाराज ने सोमवार 22 दिसम्बर को संदेश दिया कि ईश्वर की करुणा से कोई अछूता नहीं है। आचार्य देवकीनंदन मिश्रा के संयोजन में हो रहे इस वार्षिक 11वें महा अनुष्ठान में आगंतुक सौभाग्यशाली भक्तों ने सरस भजनों का भी आनंद लिया। "ब्रज में हो रही जय जयकार" भजन पर सभी भक्तों ने झूमते हुए रसास्वादन किया। इस कथा का आयोजन दोपहर 3 से रात आठ बजे तक किया जा रहा है। इसके माध्यम से स्वच्छ कमता के प्रति भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सोमवार को कथा का आरंभ मंत्रोच्चार से हुआ। उसके उपरांत आवाहन, षोडशोपचार पूजन, आरती, भजन कीर्तन किया गया। केन्द्रीय आकर्षण श्रीमद् भागवत कथा में महंत पंडित विनोदानंद शास्त्री महाराज ने भगवान कृष्ण की विभिन्न बाल लीलाओं की सजीव, प्रेरक और रंजक अंदाज में व्याख्या की। पूतना वध की लीला के माध्यम से उन्होंने संदेश दिया कि ईश्वर हर रूप में बुराई का नाश करते हैं। वे अपनी भक्ति और प्रेम को स्वीकारते हैं, भले ही उसमें छल ही क्यों न हो। पूतना वध का प्रसंग लोगों को बताता है कि भक्ति की शक्ति से राक्षस भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में भगवान केवल व्यक्ति के भाव देखते हैं। इसलिए पूतना जैसी राक्षसी को भी माता का दर्जा और दिव्य गति प्रदान की। यह प्रसंग लोगों को सीख देता है कि ईश्वर की करुणा से कोई अछूता नहीं है।

# संक्षिप्त

## महात्मा गांधी नाम से नफरत करती है मोदी सरकार-भाकपा

संवाददाता

लखनऊ। मोदी सरकार आर्थिक रुप से पंगु हो गयी है और महात्मा गाँधी ग्रामीण रोजगार योजना के लिए धन न होने कारण समाप्त कर दिया गया है।यह संघ नियंत्रित और प्रशिक्षित सरकार महात्मा गांधी नाम से नफरत करती है और वह चाहते है कि नथूनीराम गोडसे रोजगार योजना चलाई जाये, जिससे गोडसे को स्वीकार्यता दिलायी जा सके, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा बाराबंकी में पार्टी के प्रदर्शनकारियो को सम्बोधित करते हुए पार्टी के राज्य परिषद सदस्य रणधीर सिंह सुमन के कहीं। जिला सचिव बृजमोहन वर्मा ने कहा कि राज्य सरकारे खुद कर्ज के मकड़ध्जाल में फंसी हुई। वह 40 फीसदी नयी योजना में शेयर नहीं कर पायेगी और नया कानून धन के अभाव में दम तोड़ देघा।राज्य परिषद सदस्य प्रवीण कुमार ने कहा कि 70 करोड लोगो को आंशिक रोजगार देने वाले कानून समाप्त करना उनकी आर्थिक विफलता का सूचक है। किसान सभा के अध्यक्ष विनयकुमार सिंह ने कहा कि मनरेगा कानून को कम्युनिस्ट पार्टी ने बनवा था और कम्युनिस्ट पार्टी उसके लिए आन्दोलन करेगी। पार्टी के कोषाध्यक्ष शिव दर्शन वर्मा नेतृत्व में ज्ञापन राष्ट्पति को सम्बोधित जिलाधिकारी के माध्यम से दिया गया। प्रदर्शन में मो.कदीर हसन, राजकुमार वर्मा, प्रेमचद्रवर्मा, महेन्द्र यादव, धर्मेन्द्र शर्मा, प्रमेन्द्र वर्मा, सर्वेश यादव, रामनरेश वर्मा, दीपक वर्मा, सचिन्दानन्द श्रीवास्तव सुन्दरलाल सोनी, दीपक शर्मा, आशीषवर्मा, संदीप तिवारी, अमर सिंह प्रधान, राजेन्द्र बहादुर सिंह, श्याम सिंह ,रुबी सिंह चंदेल, संतोष कुमार , अंकुल वर्मा आदि प्रमुख लोग शमिल थे।

# घायल संजय सेतु के शीघ्र निर्माण की उठी मांग, विधानसभा के सामने उठी आवाज

संवाददाता

लखनऊ। विधानसभा भवन, लखनऊ के सामने सामाजिक कार्यकर्ता संजीव सिंह राठौर ने जनपद बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती व बलरामपुर के जनप्रतिनिधियों से घायल संजय सेतु (घाघरा पुल) के शीघ्र निर्माण की जोरदार मांग की। उन्होंने कहा कि संजय सेतु केवल एक पुल नहीं, बल्कि देवीपाटन मंडल की जीवनरेखा है, जिससे प्रतिदिन लाखों लोग आवागमन करते हैं। संजीव सिंह राठौर ने बताया कि पुल की जर्जर हालत के कारण आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली बच्चों, मरीजों, किसानों और व्यापारियों को लंबा वैकल्पिक रास्ता अपनाना पड़ता है, जिससे समय, धन और संसाधनों की बर्बादी हो रही है। आपातकालीन सेवाओं पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से सवाल उठाया कि घायल संजय सेतु का निर्माण आखिर कब होगा और सरकार जनता को कब राहत देगी। उन्होंने कहा कि बार–बार आश्वासन दिए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। संजीव सिंह राठौर ने प्रदेश सरकार से मांग की कि इस गंभीर जनसमस्या को प्राथमिकता देते हुए तत्काल समयबद्ध कार्ययोजना घोषित की जाए, बजट आवंटन सुनिश्चित किया जाए और निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कराया जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने भरोसा जताया कि जनप्रतिनिधि जनता की पीड़ा को समझेंगे और संजय सेतु के पुनर्निर्माण के लिए शीघ्र निर्णय लेंगे।

# भ्रष्ट-दलाल कहकर पहले किया बाहर, फिर पॉजिटिव रिपोर्ट देकर दी तैनाती; 320 निजी कर्मियों का मामला

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी सहित प्रदेशभर के आरटीओ व एआरटीओ कार्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कार्य देख रहे 320 निजी कर्मियों को पहले भ्रष्टाचार और दलाली के आरोप लगाकर हटा दिया गया। बाद में उन्हीं कर्मचारियों की पॉजिटिव रिपोर्ट लगाकर दोबारा तैनाती दे दी गई। इससे अफसरों की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं। मामले की शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच गई है। ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ा कामकाज निजी एजेंसी के पास है। पहले यह जिम्मेदारी स्मार्ट चिप कंपनी के पास थी, जिसके लखनऊ समेत प्रदेशभर में 320 कर्मचारी तैनात थे। ट्रांसपोर्टनगर आरटीओ (प्रशासन) संजय तिवारी ने परिवहन आयुक्त किंजल सिंह को पत्र लिखकर इन कर्मचारियों को भ्रष्ट व दलाल बताया। हालांकि, एक दशक से अधिक समय तक साथ काम करने के बाद अचानक लगे आरोपों पर सवाल उठे। इसके बावजूद परिवहन आयुक्त ने न तो जांच कराई और न ही शिकायतों का ब्योरा मांगा। एकतरफा कार्रवाई करते हुए कर्मचारियों को हटाने के निर्देश जारी कर दिए गए। आदेश में शर्त रखी गई कि यदि कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जाता है तो संबंधित एआरटीओ की आख्या लगेगी और कंपनी को पुलिस सत्यापन कराना होगा। इससे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। नौकरी बचाने के लिए उन्होंने अफसरों व मंत्रियों से गुहार लगाई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई।

सूत्रों का कहना है कि इसके बाद अफसरों ने मिलीभगत कर कर्मचारियों से मोटी रकम वसूली और फिर पॉजिटिव रिपोर्ट लगाकर उन्हें दूसरे जिलों में तैनात कर दिया। सवाल : भ्रष्ट से ईमानदार कैसे बने कर्मचारी जिन कर्मचारियों को दलाल और भ्रष्ट बताया गया था, वे अचानक ईमानदार कैसे हो गए। उनकी कार्यप्रणाली को संतोषजनक बताते हुए प्रदेशभर में तैनाती कैसे दे दी गई, यह बड़ा सवाल बन गया है। सूत्रों का दावा है कि पूरा मामला साजिशन उठाया गया। 3.50 करोड़ की वसूली के बाद तैनाती! परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, पूरे मामले में कर्मचारियों से मोटी रकम वसूली गई। इसमें मुख्यालय में उच्चस्तर पर तैनात एक महिला व पुरुष अधिकारी सहित कई आरटीओ व एआरटीओ की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार, कर्मचारियों से 3.50 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली हुई है। कई अफसरों पर कार्रवाई संभव परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मामले की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय पहुंच चुकी है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी अफसरों से पूछताछ करेंगे कि बिना जांच आरोप कैसे लगाए गए और फिर संतोषजनक रिपोर्ट के आधार पर तैनाती कैसे दी गई। मुख्यमंत्री कार्यालय से जांच शुरू होने पर मुख्यालय समेत कई आरटीओ अफसरों पर कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है।

# जो कहा, वह किया, और जो नहीं कहा, वह भी करके दिखाया : केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा

## निरंतर सेवा, निरंतर विकास का सशक्त मॉडल है छत्तीसगढ़ – मुख्यमंत्री

## हर वर्ग तक विकास पहुंचाना हमारा लक्ष्य : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

बीएनई

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार के सफल दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जांजगीर–चांपा जिले के खोखराभाठा पुलिस लाइन मैदान में आयोजित जनादेश परब में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने मंच से प्रदेश की उपलब्धियों, जनकल्याण और भविष्य की दिशा पर स्पष्ट संदेश दिया। वंदे मातरम और राज्यगीत के साथ आरंभ हुए कार्यक्रम में जनविश्वास, गौरव और निर्माण के संकल्प को दोहराया गया। केंद्रीय मंत्री नड्डा ने कहा कि "जो कहा था, वह किया – और जो नहीं कहा था, वह भी करके दिखाया।" उन्होंने दो वर्षों के रिपोर्ट–कार्ड को रेखांकित करते हुए बताया कि सरकार ने किसानों, महिलाओं, युवाओं और श्रमिकों के हित में संवेदनशील और परिणामकारी निर्णय लिए हैं, जिनका असर जमीनी स्तर पर दिख रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के पहले महीने में किसानों को 3700 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान और बीते दो वर्षों में 1.25 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष अंतरण अन्नदाताओं के सम्मान का प्रमाण है। भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए 5 लाख से अधिक हितग्राहियों को 10–10 हजार रुपये की सहायता दी गई, जिससे उनकी सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा मजबूत हुई। केंद्रीय मंत्री नड्डा ने कहा कि युवाओं के लिए पारदर्शी भर्ती तंत्र, 32 हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया, लोक सेवा आयोग में पारदर्शिता, नालंदा लाइब्रेरी की स्थापना और आईटीआई के आधुनिकीकरण जैसे कदमों को उन्होंने "भविष्य–निर्माण की नींव" बताया। महिलाओं के स्वावलंबन हेतु महतारी वंदन योजना और महतारी सदन, पीएम जनमन के तहत 70 लाख परिवारों को लाभ तथा धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण को उन्होंने सरकार की संवेदनशीलता का उदाहरण बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ का रेलवे बजट 22 गुना बढ़ा है, 32 अमृत स्टेशन वर्ल्ड–क्लास मानकों पर विकसित हो रहे हैं और आयुष्मान भारत, उज्ज्वला, जल जीवन मिशन, पीएम–किसान जैसी योजनाओं का व्यापक लाभ आमजन तक पहुंचा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर बधाई देते हुए कहा कि सरकार आम जनता के विश्वास पर खरा उतरने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री आवास, महतारी वंदन, भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, चरण पादुका सहित अनेक योजनाओं से विकास को गति मिली है। मुख्यमंत्री साय ने स्पष्ट किया कि नक्सलवाद की कमर तोड़ने और नक्सल–मुक्त छत्तीसगढ़ के लक्ष्य की दिशा में ठोस प्रगति हुई है। सुरक्षा, पुनर्वास और विकास – तीनों मोर्चों पर समन्वित रणनीति से शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उन्होंने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट 2047 के माध्यम से संसाधन–समृद्ध छत्तीसगढ़ को सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित राज्य बनाने का रोडमैप तय किया गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को अवसरों का राज्य मिल सके। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि जांजगीर–चांपा में जनादेश परब का आयोजन जिले के लिए ऐतिहासिक क्षण है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटियों को एक–एक कर पूरा किया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सरकार बनने के बाद 18 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं और विकास के सभी कार्यों को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे आमजन को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। वित्त मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री ओ.पी. चौधरी ने स्वागत उद्बोधन में कहा कि सरकार ने लोकतंत्र, जनविश्वास और सुशासन को सुदृढ़ किया है। विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से छत्तीसगढ़ विकास के नए मानक गढ़ रहा है। जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव ने सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर जनता को बधाई देते हुए कहा कि इस अवधि में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जे पी नड्डा ने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 2 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों के रिपोर्ट–कार्ड और "सेवा के 2 साल" पुस्तक का विमोचन किया, जिसमें सरकार की दो वर्ष की उपलब्धियों को प्रस्तुत किया गया है। कार्यक्रम के दौरान जांजगीर–चांपा की विशिष्ट पहचान को रेखांकित करते हुए कोसा और कांसा भेंटकर अतिथियों का पारंपरिक स्वागत–अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में बीते दो वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित वीडियो का प्रदर्शन हुआ। केंद्रीय मंत्री जे पी नड्डा और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विभिन्न विभागों की विकासमूलक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य, शिक्षा, महिला–बाल विकास, जल संसाधन, ऊर्जा, सहकारिता सहित कई स्टॉलों पर योजनाओं की जानकारी ली गई। मुख्यमंत्री साय ने हितग्राहियों से सीधे संवाद कर योजनाओं से जीवन में आए सकारात्मक बदलावों को सुना। कार्यक्रम में पीएम आवास योजनांतर्गत लाभार्थियों को चाबियां सौंपी गईं। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों से योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का आह्वान किया।

# एनटीपीसी सिंगरौली में हर्षोल्लास एवं सौहार्द के साथ क्रिसमस का उत्सव

बीएनई

सिंगरौली। एनटीपीसी सिंगरौली द्वारा शक्तिनगर टाउनशिप में क्रिसमस पर्व हर्षोल्लास, उल्लास और आपसी सद्भाव के वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर एनटीपीसी के कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की, जिससे पूरे परिसर में आनंद, शांति और सौहार्द का वातावरण परिलक्षित हुआ। कार्यक्रम के दौरान आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक एवं मनोरंजक गतिविधियों के माध्यम से क्रिसमस का मूल संदेशकृप्रेम, भाईचारा और मानवता–प्रभावी रूप से प्रसारित किया गया। समारोह की गरिमा परियोजना प्रमुख एवं कार्यकारी निदेशक श्री संदीप नायक की गरिमामयी उपस्थिति से और अधिक बढ़ गई। उनके साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं विभागाध्यक्ष भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री नायक ने सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएँ देते हुए आपसी एकता, सामंजस्य और पारस्परिक सम्मान के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन कर्मचारियों और उनके परिवारजनों को एक सूत्र में बाँधते हैं तथा संगठन में सकारात्मक और सहयोगात्मक कार्य संस्कृति को सुदृढ़ करते हैं। यह क्रिसमस समारोह एनटीपीसी सिंगरौली परिवार के बीच आपसी मेल–जोल को और प्रगाढ़ करने के साथ–साथ शांति, सद्भाव और सामाजिक समरसता का सशक्त संदेश देने में सफल रहा। इस अवसर पर एनटीपीसी सिंगरौली के जोसफ बास्टियन, मुख्य महाप्रबंधक (ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस), सी.एच. किशोर कुमार, महाप्रबंधक (मेंटेनेंस एवं एडीएम), रश्मि रंजन मोहंती, महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट), पीयूष श्रीवास्तव, महाप्रबंधक (रसायन बीई एवं नगर प्रशासन), सिद्धार्थ मण्डल, अपर महाप्रबंधक (मानव संसाधन), अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, वनिता समाज की सम्माननीय सदस्याएँ, एनटीपीसी कर्मचारियों के परिवारजन तथा यूनियन –एसोसिएशन के मानद प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

# मेडिकल स्टोर पर मिले कोडीन युक्त कफ सीरप के दो नमूने सील

बृजेश चतुर्वेदी

कन्नौज। दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं कोडीन युक्त तथा नारकोटिक्स दवाओं की बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से आज कन्नौज के चिड़िया गंज एवं अन्य स्थानों पर छापामार कार्यवाही की गई। कृष्णा मेडिकल स्टोर पर औचक निरीक्षण कर दो दवाओं के नमूने सील किए गए। मौके पर मिली कोडीन युक्त औषधियों के के क्रय विक्रय बिल प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया। मेडिकल स्टोर में निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों पर मौजूद प्रोपराइटर को सख्त चेतावनी दी गई तथा कोडीन युक्त दवाओं के क्रय विक्रय पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गई है। अन्य मेडिकल स्टोर संचालकों को कमियों के सापेक्ष चेतावनी दी गई। कोडीन युक्त औषधियों तथा नारकोटिक्स संबंधी औषधियों के सम्बन्ध में निर्देश दिए गए कि दवाओं को बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के न बेचे तथा क्रय एवं विक्रय का रिकॉर्ड मेंटेन करे स यदि मेडिकल संचालक दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी।

# कांग्रेसियों ने मनरेगा योजना का नाम बदलने पर जताया विरोध

## सदर तहसील परिसर में प्रदर्शन कर जताया आक्रोश

बृजेश चतुर्वेदी

कन्नौज। सदर तहसील में सोमवार दोपहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनरेगा योजना का नाम बदलने के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया।

यह प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष विजय मिश्रा और दिनेश पालीवाल के नेतृत्व में हुआ। पार्टी नेता और कार्यकर्ता सदर तहसील पहुंचे और एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मनरेगा योजना का नाम बदलना सरकार का गलत निर्णय है। उनका कहना था कि सरकार महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना के तहत गरीबों और मजदूरों को मिलने वाले काम को बंद करने की साजिश कर रही है। कांग्रेस नेता तारिक वशीर ने इस दौरान कहा कि मनरेगा योजना के तहत राज्य सरकारों को पहले 10 प्रतिशत राशि देनी होती थी। उन्होंने तर्क दिया कि उत्तर प्रदेश सहित कई राज्य पहले से ही कर्ज में हैं। केंद्र सरकार नए नियमों के तहत राज्य सरकारों से इस योजना में 40 प्रतिशत तक बजट खर्च करने की उम्मीद कर रही है। वशीर ने सवाल उठाया कि जब राज्य सरकारें 10 प्रतिशत बजट भी नहीं दे पा रही हैं, तो वे 40 प्रतिशत कैसे देंगी। उन्होंने इसे मजदूरों से रोजगार छीनने की साजिश बताया। इस प्रदर्शन में किरण वर्मा, संगीता सिंह, अहसान उल हक सहित कई अन्य नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

# भारत-न्यूजीलैंड व्यापार को पांच साल में दोगुना करने की जरूरत, जानें रिपोर्ट में एसा क्यों कहा गया

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड को चुनिंदा उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती कर अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इसके साथ ही कृषि जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। यह सुझाव थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) ने दिया। जीटीआरआई ने कहा कि सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच अधिक सीधी उड़ानें, सरल वीजा नियम और पेशेवर योग्यताओं की आपसी मान्यता अहम होगी। विशेष रूप से आईटी, स्वास्थ्य सेवा और विमानन क्षेत्रों में इससे अवसर बढ़ सकते हैं। दोनों देश अगले पांच वर्षों में बीटीए को दोगुना कर सकते हैं एजेंसी के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि दोनों देश चुनिंदा उत्पादों पर शुरुआती टैरिफ राहत, व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों के आदान–प्रदान और कृषि, वानिकी, फिनटेक व शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सेक्टोरल सहयोग के जरिए अगले पांच वर्षों में दोतरफा व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय कर सकते हैं। भारत–न्यूजीलैंड के बीच जल्द हो सकता है एफटीए

भारत और न्यूजीलैंड एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत के समापन की घोषणा करने वाले हैं। इसके लिए बातचीत 2010 में शुरू हुई थी, फिर नौ दौर के बाद 2015 में रुक गई थी और इस साल फिर से शुरू की गई थी।इस वर्ष 5 से 9 मई को वार्ता का पहला दौर आयोजित किया गया था। दोनों देशों के लिए क्यों है यह समझौता अहम? श्रीवास्तव ने कहा कि यह समझौता वस्तुओं पर शुल्क कम करने, सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने और व्यापार सुविधा को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जबकि राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों, विशेष रूप से डेयरी क्षेत्र में नीतिगत गुंजाइश को बनाए रखेगा। उन्होंने आगे कहा कि इस समझौते के तहत, औद्योगिक उत्पादों, वस्त्रों, इंजीनियरिंग सामानों, ईंधनों और कुछ कृषि उत्पादों की एक विस्तृत शृंखला पर शुल्क समाप्त या काफी कम होने की उम्मीद है। वहीं संवेदनशील कृषि उत्पादों को बहिष्करण सूचियों, शुल्क–दर कोटा और लंबी चरणबद्ध समाप्ति अवधि के माध्यम से संरक्षित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सीमा शुल्क सुविधा, मानकों, लघु व मध्यम उद्यमों, स्थिरता और विवाद निपटान संबंधी प्रावधानों के साथ–साथ सेवा प्रतिबद्धताओं से आईटी, व्यावसायिक सेवाओं, शिक्षा और डिजिटल व्यापार में सहयोग गहरा होने की संभावना है। श्रीवास्तव ने कहा कि भारत के लिए, यह समझौता प्रशांत क्षेत्र के उच्च आय वाले, नियम–आधारित बाजार तक पहुंच को मजबूत करता है और इसकी व्यापक इंडो–पैसिफिक आर्थिक रणनीति का समर्थन करता है। न्यूजीलैंड के लिए, यह वैश्विक व्यापार अनिश्चितता में वृद्धि के बीच दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक में अधिक सुरक्षित प्रवेश प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2025 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 1.3 अरब डॉलर रहा वित्त वर्ष 2025 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 1.3 अरब डॉलर था (भारत का निर्यात 711.1 मिलियन डॉलर और आयात 587.1 मिलियन डॉलर था)। न्यूजीलैंड का औसत आयात शुल्क केवल 2.3 प्रतिशत है, जबकि भारत का 17.8 प्रतिशत है, और न्यूजीलैंड की 58.3 प्रतिशत टैरिफ लाइनें पहले से ही शुल्क–मुक्त हैं। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि भारतीय निर्यातकों को पहले से ही पर्याप्त पहुंच प्राप्त है, जबकि भारत शुल्क कटौती के माध्यम से समायोजन का अधिकांश भार वहन करेगा। क्या कहते हैं आंकड़े? न्यूजीलैंड को भारत का निर्यात व्यापक है, लेकिन इसमें ईंधन, वस्त्र और फार्मास्यूटिकल्स की मात्रा अधिक है। विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) का शिपमेंट 110.8 मिलियन डॉलर के साथ सबसे आगे रहा, इसके बाद कपड़े, फैब्रिक और घरेलू वस्त्रों का शिपमेंट 95.8 मिलियन डॉलर का रहा। दवाओं का मूल्य 57.5 डॉलर था, जबकि टर्बोजेट सहित मशीनरी का योगदान 51.8 मिलियन डॉलर था।

# धुरंधर की सफलता के बाद नए साल का जश्न मनाने निकले रणवीर सिंह,

## पत्नी दीपिका का हाथ थामे एयरपोर्ट पर आए नजर

एजेंसी

साल के आखिर में बॉलीवुड के सबसे चर्चित और पावर कपल रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। वजह है– रणवीर की फिल्म 'धुरंधर' की जबरदस्त बॉक्स ऑफिस सफलता और उसी बीच कपल का न्यू ईयर वेकेशन के लिए रवाना होना। सोमवार सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर दोनों को परिवार के साथ देखा गया, जहां से चुपचाप दोनों न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए रवाला हुए। एयरपोर्ट पर नजर आए रणवीर और दीपिका एयरपोर्ट पर रणवीर और दीपिका हाथों में हाथ डाले नजर आए। दोनों ने एक–दूसरे को कॉम्प्लिमेंट करता हुआ लुक चुना– डार्क आउटफिट्स, ओवरकोट और सनग्लासेस। रणवीर ने अपने स्टाइल में बीनी कैप जोड़कर इसे कैजुअल टच दिया, वहीं दीपिका ब्लैक ट्राउजर्स और क्लासिक एलिगेंस के साथ बेहद ग्रेसफुल दिखीं। कैमरों के सामने रणवीर की मुस्कान साफ बता रही थी कि श्धुरंधरश की सफलता का असर उनके चेहरे पर झलक रहा है। रणवीर के परिवार के सदस्य भी आए नजर थोड़ी देर बाद रणवीर के परिवार के सदस्य– पिता जगजीत सिंह भावनानी, मां अंजू भावनानी और बहन रीतिका भावनानी भी एयरपोर्ट पर नजर आए। सभी ने पैपराजी को मुस्कुराते हुए पोज़ दिए। इस पूरे सीन को देखकर यही कयास लगाए जा रहे हैं कि परिवार धुरंधर की कामयाबी के जश्न और नए साल के स्वागत के लिए छुट्टियों पर निकल पड़ा है। धुरंधर बनी रणवीर के करियर की सबसे बड़ी हिट

वर्क फ्रंट की बात करें तो आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में शुमार हो चुकी है। 5 दिसंबर को रिलीज हुई यह स्पाई–थ्रिलर भारत में 500 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है, जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 800 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। फिल्म में रणवीर ने एक भारतीय जासूस का किरदार निभाया है, जो पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी नेटवर्क में घुसपैठ करता है। कहानी, स्केल और परफॉर्मेंस– तीनों स्तर पर फिल्म को जबरदस्त सराहना मिली है। धुरंधर की स्टारकास्ट 'धुरंधर' में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, अक्षय खन्ना और सारा अर्जुन जैसे कलाकारों की मौजूदगी ने फिल्म को और मजबूत बनाया। दर्शकों का मानना है कि रणवीर ने इस फिल्म के जरिए खुद को एक बार फिर इंडस्ट्री के टॉप पर साबित कर दिया है। बता दें फिल्म की सफलता के बाद रणवीर की यह पहली पब्लिक अपीयरेंस थी।

# रुपये की कीमत में गिरावट से घबराएं नहीं, बदलें निवेश की रणनीति, बनाएं डॉलर फ्रेंडली पोर्टफोलियो

एजेंसी

नई दिल्ली। 2025 भारतीय रुपये के लिए भारी उथल–पुथल भरा रहा है। विदेशी निवेशकों की रिकॉर्ड बिकवाली और वैश्विक अनिश्चितता के बीच रुपया 91 रुपये प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर तक गिर गया। लेकिन एक निवेशक के तौर पर यह घबराने का नहीं, बल्कि अपनी निवेश रणनीति को बदलने का समय है। गिरता रुपया सिर्फ महंगाई नहीं लाता, बल्कि समझदार निवेशकों के लिए डॉलर से कमाई के दरवाजे भी खोलता है। बस जरूरत है सही सेक्टर चुनने की।

रुपया पहली बार 91 के पार, शेयर बाजार में भारी उतार–चढ़ाव। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज देखकर मोहित के पसीने छूट गए। मोहित को लगा बरसों की बचत कहीं डूब न जाए। अपने वित्तीय सलाहकार को तुरंत फोन लगाया और पूछा, पोर्टफोलियो लाल निशान में है। क्या मुझे अपना सारा पैसा निकाल लेना चाहिए? मोहित की तरह यह सवाल तमाम निवेशकों के मन में है। बाजार की इस अस्थिरता को डर नहीं, बल्कि अवसर की तरह देखना चाहिए। पिछले एक साल में भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 6. 86 फीसदी कमजोर हुआ है। 19 दिसंबर, 2024 को रुपया 85.09 के स्तर पर था। 16 दिसंबर को रुपये ने पहली बार डॉलर के मुकाबले 91.19 का स्तर छुआ।

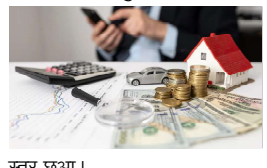

इस कमजोरी के पीछे मुख्य कारण : विदेशी निवेशकों (FIIs) की लगातार बिकवाली (दिसंबर में अब तक 18,667 करोड़ रुपये)

अमेरिका–भारत व्यापार तनाव

वैश्विक स्तर पर डॉलर की मजबूती

रुपये में आई कमजोरी ने निवेशकों के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है– अब निवेश की दिशा क्या हो?

जब रुपया कमजोर होता है, तब कुछ सेक्टर 'सुरक्षा कवच' की तरह काम करते हैंरू

आईटी सर्विसेस : टीसीएस, इंफोसिस जैसी कंपनियों की आय डॉलर में होती है, खर्च रुपये में। रुपया गिरने से इनका मार्जिन अपने आप बढ़ जाता है।

फार्मा सेक्टर : सन फार्मा और सिप्ला जैसी कंपनियां अमेरिका और यूरोप को भारी निर्यात करती हैं, जिससे उन्हें मुद्रा लाभ मिलता है।

इंजीनियरिंग और केमिकल्स : भारत फोर्ज और पीआई इंडस्ट्रीज जैसे निर्यातकों के लिए कमजोर रुपया ऑर्डर बुक की वैल्यू बढ़ाने वाला साबित होता है।

खाद्य और कृषि उत्पाद : कम आयात निर्भरता के कारण चावल, चीनी और समुद्री उत्पाद निर्यातकों को सीधा लाभ मिलता है।

धातु : स्टील और एल्युमीनियम की कीमतें वैश्विक स्तर पर डॉलर में तय होती हैं, जिससे टाटा स्टील और भ्पदकंसबव जैसे निर्यातकों को फायदा होता है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **धर्मेन्द्र सिंह** द्वारा शौर्य प्रिंटर्स, शिवपुरी कालोनी, निकट बांसमण्डी चौराहा, लखनऊ से मुद्रित तथा एमआईजी-47, सेक्टर-ई, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) से प्रकाशित
**सम्पादक-अंजू सिंह** (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा) Email-lkojunction@gmail.com. RNI NO.-UPHIN/2015/64743